

विचार बिन्दु

आत्मा के आनंद रूपी सामंजस्य का बाहरी रूप दया है। –विलियम हैज़लित

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति

राजस्थान, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाना जाता है, आज शिक्षा और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह रेगिस्तानी राज्य, जहां कभी जल और संसाधनों की कमी ने विकास को चुनौती दी थी, अब शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के बल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान ने शिक्षा को सुलभ, समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की शक्ति का उपयोग प्रमुख है।

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई, लेकिन इसकी नींव काफी पहले पड़ चुकी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश भर में शिक्षा में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने का रास्ता खोला, और राजस्थान ने इसे उत्साहपूर्वक अपनाया। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल मंचों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। मिशन बुनियाद इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे 2022 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, लैंगिक असमानता को कम करना और स्कूल छोड़ने की दर को घटाना था। इस पहल के तहत लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्रदान की गई। यह कार्यक्रम छह जिलों—उदयपुर, सिरोंही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ, जहां कक्षा 8 से 12 के 24,360 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और उनकी सीखने की क्षमता में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह परिणाम इस बात का सबूत है कि डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी हो सकती है। राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया गया है।

हाल ही में, 13,976 राजकीय विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब्स स्थापित की गई हैं, जो छात्रों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ रही हैं। इसके साथ ही, 13,018 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, जहां इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई को रोचक और आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री गंगागर जिले में राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल शुरू किया गया, जो इस दिशा में एक मील का पथर साबित हुआ। ये पहल न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं, बल्कि ग्रामीण स्कूलों को भी डिजिटल संसाधनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि शिक्षा की पहुंच हर कोने तक हो। हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद, राजस्थान में डिजिटल शिक्षा के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी। रेगिस्तानी भूभाग और बिखरी हुई आबादी के कारण कई गांवों में अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा नहीं है। इसके अलावा, बिजली की अनियमित आपूर्ति डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बाधित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, जैसे पर्याप्त कक्षा या प्रशिक्षित शिक्षक, भी कमी हैं, जिसके कारण डिजिटल शिक्षा का प्रभाव सीमित हो जाता है।

शिक्षकों का तकनीकी प्रशिक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। कई शिक्षक, विशेष रूप से पुराने शिक्षक, डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण विधियों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो समय और संसाधनों की मांग करते हैं। आर्थिक असमानता भी डिजिटल शिक्षा के सामने एक बड़ा रोड़ा है। कई परिवारों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट डेटा खरीदने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन कक्षाओं में उनकी भागीदारी कम रहती है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह समस्या और भी स्पष्ट हो गई थी, जब ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र विकल्प थी, लेकिन कई छात्र इससे वंचित रह गए। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक मुद्दा है। न केवल छात्रों, बल्कि अभिभावकों को भी डिजिटल उपकरणों के उपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। इन चुनौतियों के बावजूद, राजस्थान ने इनका सामना करने के लिए कई रचनात्मक उपाय किए हैं, जैसे ऑफलाइन डिजिटल सामग्री प्रदान करना और सामुदायिक स्तर पर डिजिटल सेंटर्स स्थापित करना। भविष्य की बात करें तो राजस्थान में डिजिटल शिक्षा की संभावनाएं अपार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राज्य सरकार ने 2025 तक कक्षा

स्टार लिंक जैसी सुविधाओं के लिए सरकार को अभी है खाका तैयार कर लेना चाहिए ताकि दूर संचार के क्षेत्र में राजस्थान धमाकेदार एन્ટ्री करें और स्कूली शिक्षा का कायाकल्प हो। चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, लेकिन इनका समाधान रचनात्मक और समावेशी दृष्टिकोण से संभव है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री जैसे नवाचार राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएंगे।

में पढ़ाई को चुनौतीपूर्ण पाते हैं। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रमों में चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वैश्विक तकनीकी संसाधन जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, राजस्थान के स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योगदान दे रही हैं। ये कंपनियां क्लाउड-आधारित शिक्षण मंच और डिजिटल उपकरण प्रदान कर रही हैं, जो शिक्षण को और प्रभावी बना रहे हैं। विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी राजस्थान में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहयोग न केवल तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराता है, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों के डिजिटल शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेकर राजस्थान अपने पाठ्यक्रम को और नवाचारी बना सकता है। इस डिजिटल क्रांति के पीछे कई नायक भी हैं, जिन्होंने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध और संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर जैसे कदम उठाए गए हैं, जो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और मूल्य-आधारित बनाने की दिशा में हैं। इसके अलावा, कई गैर-सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, केवल्यू एजुकेशन फाउंडेशन ने मिशन बुनियाद को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हजारों छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा। स्थानीय स्तर पर, कई शिक्षक भी अपने सीमित संसाधनों के बावजूद डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। सरकार की भूमिका इस क्रांति को गति देने में सबसे महत्वपूर्ण रही है। राजस्थान सरकार ने न केवल नीतिगत स्तर पर बदलाव किए, बल्कि कार्यान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया।

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों में नीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को चार श्रेणियों-कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12-में संगठित करने की योजना बनाई, ताकि शिक्षा का ढांचा और सुसंगत हो। इसके अलावा, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए राजस्थान डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, ताकि वे तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकें।हालांकि, सरकार के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट आवंटन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास और शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर और काम करने की जरूरत है। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा के दीर्घकालिक प्रभाव को मापने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल शिक्षा केवल तकनीकी संसाधनों तक सीमित न रहे, बल्कि यह छात्रों के समग्र विकास में योगदान दे। राजस्थान में शिक्षा और डिजिटल क्रांति का सफर अभी शुरूआती दौर में है, लेकिन इसकी दिशा और गति उत्साहजनक है। मिशन बुनियाद, आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम और विदेशी सहयोग जैसे कदम इस दिशा में मजबूत नींव रख रहे हैं। आज अन्य प्रदेशों से सींग लेते हुए राज्य में पहली कक्षा से ही एआई को शिक्षा में जोड़ने की जरूरत है। स्टार लिंक जैसी सुविधाओं के लिए सरकार को अभी से खाका तैयार कर लेना चाहिए ताकि दूर संचार के क्षेत्र में राजस्थान धमाकेदार एन्ट्री करें और स्कूली शिक्षा का कायाकल्प हो। चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, लेकिन इनका समाधान रचनात्मक और समावेशी दृष्टिकोण से संभव है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री जैसे नवाचार राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएंगे। इस क्रांति के नायक चाहे वे शिक्षक हों, नीति निर्माता हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, सभी एक ही दिशा में ले जा रहे हैं, जहां शिक्षा न केवल सुलभ होगी, बल्कि यह हर बच्चे के सपनों को साकार करने का माध्यम भी बनेगी। सरकार की सक्रिय भूमिका और समाज के सहयोग से, राजस्थान निश्चित रूप से डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सकता है।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र मोहन शर्मा साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक

राशिफल

बुधवार 22 मई, 2025



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरु-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा विद 2:17 से रात्रि 1:31 तक है। आज पंचक है। आज से राष्ट्रीय ज्येष्ठ मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:21 तक, चर 10:42 से 12:23 तक, लाभ अमृत 12:23 से 3:45 तक, शुभ 5:26 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:07



मे़ष

आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्याह्न पूर्व में आर्थिक मामलों में उचित सफलता मिल सकती है। दिन के मध्याह्न पश्चात अनावश्यक धन खर्च होगा।



तुला

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार होगा।



वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।



वृश्चिक

परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशवासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।



धनु

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।



कर्क

व्यक्तिगत पेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात अटक हुए कार्य बने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आवासन प्राप्त होगा।



मकर

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।



सिंह

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।



कुंभ

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बने लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकेंगे हैं।



कन्या

आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



मीन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खर्च होगा। दिन के मध्याह्न पश्चात वर्तमान में चल रही पेशानियां दूर होने लगेगी।



महावीर सिंह

पाकिस्तान के समर्थन-उकसावे से आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में गई, 26 निर्दोष पर्यटकों की विभत्स, अमानवीय, अधार्मिक हत्या की घटना के बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध समुचित दंडनीय कार्यवाही की ही जानी थी। पहलगांव घटना की लगभग विष्व के सम्पूर्ण सभ्य समाज द्वारा भर्त्सना की गई। चीन ने भर्त्सना को भी किन्तु संयम बरतने की सलाह के साथ, त्रुैक्य व अजरबैजान ने खुलकर भर्त्सना नहीं की। भारत के निकट पड़ोसियों ने भी घटना को मात्र हल्की से आलोचना कर ठंडा सा व्यवहार ही दिखाया। बहुत से भारतीयों की नजर में यह गम्भीर बात है और भारत की शक्तिशाली सरकार को इस और गम्भीररता से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों?

पहलगांव घटना 22 अप्रेल 2025 को घटी। भारत द्वारा कार्यवाही की गई 7 मई की रात्रि को। भारत द्वारा पाकिस्तान को दंड देने के स्वरूप पाकिस्तानी पंजाब व पीओके के चिन्हित 22 में से 9 आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण व ठहराव स्थानों, आर्थिकियों के भारत में घुसने के लॉचपैडस को ध्वस्त कर दिया गया, यह देश के शौर्य, प्लानिंग और अचूक निशानों का नतीजा था। भारत का हर नागरिक भारतीय सेना की उत्कृष्टता, बहादुरी, पेशेवराना व विधिसम्मत कार्यशैली को नतमस्तक होकर अभिवादन, सलाम, नमाम करता है।

निश्चित: इतनी बड़ी कार्यवाही के लिए सटीक सूचनाओं को एकत्र कर, उनको मध्यनजर रखकर पूरी योजना बनानी पड़ती है, योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयारी करनी पड़ती है। विभिन्न महकमों व सेना के विभिन्न अंगों की कार्यवाहियों में समन्वय बैठना पड़ता है। इसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। इसमें 1.5 दिन का समय लगा।

यहां एक सामान्य नागरिक के मन में एक सद्भावनी प्रश्न तो उठता है—ऐसा लगता है कि शायद, भारत के पास आतंकी घटना के घटने के कुछ ही घण्टों में तुरंत कार्यवाही की कोई समुचित, सुविचारित, पूर्वनिर्धारित कार्य योजना नहीं है।

15 दिन के समय में पाकिस्तान और उनके द्वारा तैयार आतंकियों को अपने आप को सुरक्षित करने और भारत की जवाबी कार्यवाही से होने वाला नुकसान को कम से कम हो इसके लिए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया होगा। उनका नुकसान

भी कम से कम ही हुआ होगा।आतंकी मरने की प्रतीक्षा थोड़े ही कर रहे होंगे। कहने वाले कह सकते हैं कि बाहर बैठ कर सीख देना सबसे आसान काम है। हां काफी हद तक यह ठीक भी है। किन्तु दूसरा पक्ष है कि वर्तमान में हमारे सेटेलाइट्स पाकिस्तान का, लगभग पूरा भूगोलिक क्षेत्र, हर समय, कवर करते हैं। उनसे प्राप्त चित्रों के सतत परीक्षण से आतंकी ठिकानों और वहां हो रही गतिविधियों की रियलटाइम ट्रैकिंग सम्भव लगती है। पाकिस्तान लगातार मुंबई की आतंकी घटना, संसद पर हमला, पठानकोट, पुलवामा, उरी व पहलगांव जैसी आतंकी कार्यवाही करता आ रहा है। गितत 10 वर्षों में की गई सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान नही सुधरा। तो फिर पाकिस्तान को सदैव के लिए स्थायी सूचना दे दी जाए कि यदि उसकी धरती से कोई आतंकी घटना भारत पर हुई तो तत्काल अन्य विधि सम्मत सभी प्रकार कार्यवाहियों के साथ साथ, समुचित हवाई हमले किए जाएंगे।

इसके लिए आतंकी ठिकानों की दिन-प्रतिदिन आधार पर सही सूचनाएं इकट्ठी करते रहना होगा और तत्काल जवाबी कार्यवाही करनी होगी। अगर हमारे सुरक्षा सलाहकारों, विशेषज्ञों का जमावड़ा इसे सम्भव नहींनमत है तो फिर नियति यही है कि पहले पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकी घटना करे और फिर हम 10-15 दिन में उसे सबक सिखा दें और फिर बैठ जाएं।ऐसा कम तक? 7 मई और 10 मई के बीच कई बार पाकिस्तानी सेना में अंतर्राष्ट्रीय सीमा व लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बेजा हरकत करते हुए भारतीय सेना व बेगुनाह नागरिकों पर भारी तोपखाने, ड्रोन्स व मिसाइलरान से से हमले किये गए।इस गम्भीर, अवांछनीय हरकत का भारत की सेना ने भी मुनासिब कार्यवाही कर प्रत्युत्तर दिया।इसी कार्यवाही में 10 मई की रात्रि व सुबह पाकिस्तान के 11 बेहद महत्वपूर्ण हवाईअड्डों को पाकिस्तान वायु सेना के लिए अनुपयोगी बना दिये अर्थात एक तरह से पाक वायुसेना को नुमाइसी खिलोने जैसा बना दिया। इनमें रावलपिंडी का हवाईअड्डा (नुरखान एयरबेस) उस स्थान के अत्यंत समीप बताया गया है जहां पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार बताया जाता है।

माना जाता है कि इसके बाद ही पाकिस्तान नें अमरीका सहित कुछ देशों से भारत के हमले रकवाने का अनुरोध किया। भारतीय पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स ने भारतीय समक्ष से वार्ता की और युद्ध रोकने का अनुरोध किया। उसके बाद युद्ध रोकने की सहमति बनी जिसकी घोषणा भारत के विदेश सचिव ने 10 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जिसका सार था कि उस रोज 5 बजे से युद्ध कार्यवाहियां रोक दी गईं। वैसे अनपढ़ भारतीय भी जनता है कि भारत की सेना कोई पाकिस्तान की सेना की तरह, थोड़ा ही है जहां सेना युद्ध शुरू और रोकने के लिए बिना सरकार की सहमति/

अनुमति के कोई भी निर्णय ले लेती है।। भारत में ऐसे निर्णय जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं अर्थात भारत की सरकार ने 10 मई 2025 को सांयकाल 5 बजे से जल, थल, वायु से कोई युद्धक कार्यवाही न करने सम्बन्धी पाकिस्तानी अनुरोध को मान लिया। सरकार से इसे युद्ध विराम के बजाए संघर्ष विराम कहना ज्यादा पसन्द करती है। लेकिन यहां किसी ने कुछ भ्रम पैदा कर दिया----भारत के परम मित्र अमरीका के कुछ उच्चपदस्थ मित्र लोगों ने। वहां के विदेश मंत्री मार्क रबियो ने कहा कि उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और उनसे संयम बरतने की अपील की। भारत ने तो उनसे यह अनुरोध किया नहीं होगा क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी उनके रहते भारत को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका अर्थ है कि ऐसा करने के लिए उनसे पाकिस्तान नें अनुरोध किया होगा। यहां तक भी ठीक है। विषय में जब जहां कही युद्ध की स्थितियां होती है तो कुछ देश लड़ने वाले देशों से शांति की अपील करते रहते हैं-कुछ गम्भीरता से तो कुछ यों ही विदेशी नीति की एक रूढ़िना कार्यवाही के रूप में।

पहला गम्भीर प्रश्न तो यह है कि भारत नें यह अनुरोध क्यों माना? भारत के उच्चपदस्थ कई युद्धवीर नेता लोग, उनके अतिकारीबी धर्माचार्यों, कुछ सांस्कृतिक संगठनों के महर्तों ने तो यह घोषणा तक कर रखी थी कि अतिशीघ्र निकट भविष्य में तो बस लिया ही मानो। भारत की संसद कई प्रस्तावों के मालूम से यह दोहरा चीक की इच्छा भारत का अभिन्न हिस्सा है। संसद में कि बार छाती ठोक के कहा गया है कि विलय के समय युद्ध विराम की 2-4 दिन की जल्दबाजी की जो गलती तत्तमय के हुक्मरानों ने की उसे सुधारने का समय आ गया है।

7 से 10 मई के बीच रोटल हुआ और जिस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जैसा, एक तरह से आंखों देखा सा प्रयास रहा रहे थे, उस से तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान हथियार डालने ही वाला था। फिर यह अमरीकी अनुरोध मानने का क्या अर्थ? हमारे बयानवीर नेता लोग तो बेचारे धक् गाए यह बताते बताते कि लड़ाई रोकने के लिए किसी का कोई वाहरी दबाव नहीं था, कोई व्यापार की बात कह कर युद्ध विराम नहीं कराया गया--केवल व केवल पाकिस्तान गिड़गड़ाया तब भारत नें दया दिखा कर बड़े भाई साहब वाला रोल अदा किया।संघर्ष विराम किया है, ओप्रेसन सिंदूर अब भी चालू है अर्थात----- (जैसा आम चाहे वैसा अर्थ निकालो)। अब यह मीडिया रिपोर्टिंग और संघर्ष विराम की कहानी इतनी की होती तब तक ठीक थी। हमारे जैसे लोगों ने तो बिना मीन हमारे के मान लिया था कि जो हमारी सरकार कह रही है वही 100 टक्का सही है। किंतु बीच में कूद पड़े, हमारे नेता भाई साहबों के परम मित्र ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प भाई साहब घोषित रूप से भारत

के परम मित्र है, जिनके लिए यहां से वहां तक पलक पांवड़े बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे विदेश सचिव जी नें संघर्ष विराम वाली घोषणा की उसके लगभग साथ सी ही, ट्रम्प भाई जान कुछ कुछ इस प्रकार के अर्थ वाली बात कह बैठे कि उनके अधिकारियों जे डी वेन्स व मार्क रबियो ने अथक प्रयास कर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करा दिया। कोई अत्यंत बड़ी विनाशकारी दुर्घटना हो सकती थी। उस से पहले ही व्यापार का हवाला देकर, होने वाली अत्यंत भयानक घटना रकवा दी।

अब भारत के अधिकारी लोग कहते रहें कि किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल संघर्ष विराम में नहीं किन्तु ठाले बैठे विपक्ष तो तो एक मुद्दा पकड़ा ही दिया न ट्रम्प भाई जान नैं। अगर एक बार कह के रूक जाते तो भी बात बनी रहती किन्तु ट्रम्प भाई साहब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे--अमरीका में कहा सो कहा विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं वहां भी कुछ कुछ ऐसा ही कह देते हैं। अब तक 6-7 बार घूमा फिरा कर ऐसा स्पष्ट रूप से या सांकेतिक रूप से कह चुके हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लेमी भी पाकिस्तान में आकर कह गए कि ब्रिटेन अमरीका के साथ काम करते हुए भारत पाकिस्तान के मध्य मुद्दे सुलझाने का प्रयास करता रहेगा। इस से भी प्रश्न होता है कि कोई ऐसी बात हुई क्या? अब यहां के कद्दावर नेताओं ने तो पूरा जोर लगा रखा है यह समझने के लिए कि ट्रम्प भाई साहब तो यों ही बोलते रहते हैं, उन्हें कोई सिरिसली नहीं लेता। यह लोग गिना रहे हैं कि पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में वर्ष बार कितनी कितनी बार खुट बोले ट्रम्प भाई साहब।

अब 19 मई 2025 को विदेश सचिव नें यह कहा है कि ट्रम्प स्वमेव बीच में आ रहे हैं तो हम क्या करें। यहां के कुछ मंदबुद्धि लोग और सत्ताधारियों की नजर में कुछ कुछ देशद्रोही टाटप लोग यों ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इस वस्तु राष्ट्र प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है कि सरकार की कही बात को 100 टक्का सही मानना ही है। लेकिन फिर भी कुछ सिरफिरे लोग इस बात को ऐसे ही आगो गयी होने ही नहीं दे रहे। चलो छोड़ो जी, यह तो बड़े लोगों की बातें हैं। एक-दूसरे की टांग, पूँछ, मूछ जो हाथ लगे सो खींचना इन बड़े नेताओं का पसंददीदा खेल बन चुका है लेकिन मेरे गांव का आदमी भी कुछ अटपटे सवाल पूछ लेता है जिनका मेरे जैसे स्वघोषित परम् राष्ट्रवादी के पास भी कोई जवाब नहीं:---(1) बैसर्न घाटी में जहां 2-3 हजार पर्यटक हर रोज जा रहे थे, सुरक्षा से अन्य सुविधाओं की घोर अनदेखी क्यों थी? (2) 26 पर्यटकों के मौत के जिम्मेदार को 3-4 आतंकी,आखिर कब तक पकड़े जाएंगे? मार दिए गए या पाकिस्तान में प्रवेश कर गए? (3) ट्रम्प भाई जान बार बार क्यों कह देते हैं, उन्होंने खुद रकवाया, आर्थिक युद्ध का खुद टलवाया, किसी न्यूट्रल देश में वार्ता का प्रस्ताव दिया वगैरा वगैरा जिसे

अखबारों नें कुछ थो छापा है:--

"Donald Trump claims he stopped India Pakistan nuclear war."Told them gonna do a lot of trade with you"(gonna means I am going to--in general speaking)

Trump once again claims he helped settle India - P a k tensions,--used trade as leverage.

This is the sixth time since Saturday that Trump has claimed that the US brokered the ceasefire between New Delhi and Islamabad."

सवाल और भी थे गांव के लोगों के ----

(4) ठाले बैठे लोगों के पास और नहीं तो यही सवाल है कि पुलवामा के हमलों की सुरक्षा चुक का क्या खुलासा हुआ व चूक पर क्या कार्यवाही हुई (5) यही भी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार खुद ही प्रश्न का उत्तर उचित स्तर से दे तो आगे सवाल उठे ही नहीं, क्या कारण है, क्यों ऐसा नहीं किया जाता? सनसडबळ विशेष सत्र बुलाकर सारी बातने योग्य बातें संसद में बता दे---क्यों आम आदमी या विपक्ष के सवालों को सेना के शौर्य पर शक का मुलमा चढ़ा कर दफन कर दिए जाते हैं और सवाल करने वालों को देशद्रोही तक कह जाता है? क्या जो सवाल देश की जनता के मन में हैं वैसे सवाल अभी विभिन्न देशों में भेजे जा रहे संसदों से वहां का मीडिया नहीं पूछेगा--उनको तो देश द्रोही कहलाने का डर होगा नही!

इस देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे देश की सेना के शौर्य, अनुशासन, पेशेवर सक्षमता, वीरता पर भरोसा नहीं हो किन्तु ऐसा दावा कई नेताओं की देश के प्रति निष्ठा और प्रेम के सम्बंध में निर्विवाद रूप से नहीं किया सकता क्योंकि उनके बोल व कर्म कई बार संशय उत्पन्न करते हैं। ओर जाते जाते, दिल्ली स्थित विकासशील देशों के दूतावास हमारे बड़बोले नेताओं के एक एक बयान, वाक्य, भावभंगिमाओं का विश्लेषण कर अपनी सरकारों को ब्रीफ भेजते हैं और उन देशों के नेता उन्हें ध्यान में रखकर ही हमारे नेताओं से ठक्कर सुहाती बातें करते है। विभिन्न देशों के बीच रिश्तों व राजनीति के विधान, विश्लेषक, ज्ञाता मोरगनथा के अनुसार

"राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध एक शक्ति संघर्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्र-राज्य मुख्य अभिनेता हैं। उनका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। राष्ट्र की शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। राज्यों को शक्ति और नीतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।" शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच के रिस्ते गलतबाहियों से तय नहीं होते।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

- ग्राम पंचायत नान्दला, बुबानिया और धोलादांता बुबानिया के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को ज्ञापन साँपा**
- नगर पालिका में विलय के बाद से काम रुके हुए हैं, सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे ग्रामीण**

हो गई हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने

की प्रक्रिया भी रुकी हुई है और यदि समय पर कार्या शुरू नहीं हुए तो बहुत

से परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी से मांग की है कि ग्राम पंचायत नान्दला एवं संबंथित गांवों के जन आधार व राशन कार्ड संबंधी कार्यों को शीघ्र पुनः प्रारंभ करया जाए, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

जन आधार व राशन कार्ड सेवाएं नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान

नसीराबाद, (निसं)। ग्राम पंचायत नान्दला, बुबानिया और धोलादाता बुबानिया के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी, नसी